वैश्विक पानी की कमी का बढ़ता दबाव

विश्व बढ़ते जल संकट का सामना कर रहा है। पिछले साल अगस्त में अरल सागर का पूर्वी हिस्सा 600 वर्षों में पहली बार पूरी तरह से सूख गया। कैलिफोर्निया पिछले तीन सालों से सूखे का सामना कर रहा है। जनांकिक परिवर्तन और अवहनीय आर्थिक क्रियाकलापों के चलते उपलब्ध पानी की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित हुई है। तेज़ शहरीकरण के कारण पानी के उपयोग तथा पानी सम्बंधी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बना, जिसके असर शहरी वातावरण और मानव स्वास्थ्य पर होना लाज़मी है। इन सब बदलावों ने पानी को महंगा और दुर्लभ बना दिया है, विशेष रूप से गरीब और हाशिए के लोगों के लिए।

2050 तक पानी की मांग 40 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। और 2025 तक 1.8 अरब लोग ऐसे देशों या क्षेत्रों में बसे होंगे जहां पानी दुर्लभ होगा और दो-तिहाई आबादी को साफ पानी नहीं मिल सकेगा। अलबत्ता नज़ारा पूरी तरह अंधकारमय नहीं है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के लिए जो संसाधन जुटाए गए हैं उनके चलते 2 अरब लोगों को जल स्रोतों में सुधार का लाभ मिला है।

फिर भी यह ध्यान रखना होगा कि 75 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी मयस्सर नहीं है। लगभग 80 प्रतिशत तक गंदा पानी बिना उपचारित किए समुद्रों, नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है। हर साल 5 साल से कम उम्र के करीब 20 लाख बच्चे साफ पानी और उचित शौच व्यवस्था के अभाव के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। 22 देशों में रहने वाले एक अरब लोग खुले में शौच करते हैं। ढाई अरब लोगों के पास पर्याप्त मल निपटान की व्यवस्था नहीं है।

यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। शौचालय और खुले में शौच को लेकर चुप्पी तोड़ना होगा। ये शब्द विकास शब्दावली के अभिन्न अंग होने चाहिए।

आज के युग में हम देखते हैं कि पानी की कमी टकरावों को बढ़ावा देती है और शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

पानी तक पहुंच में गिरावट के चलते सामाजिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता और शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात तब होगी जब इसे एक हथियार के तौर पर युद्ध में इस्तेमाल किया जाएगा।

यह बात सूडान में हुए डारफुर विवाद में पहली बार नज़र आई थी। 2007 में उत्तरी डारफुर के एक गांव में महिलाएं पानी-पानी चिल्ला रही थीं। पता चला कि दुश्मन मिलिशिया ने पानी के कुओं में ज़हर डाल दिया है और उन्हें मजबूरन जाकर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है।

इराक में, उग्रवादी समूह ISIL ने पानी की उपलब्धता का इस्तेमाल पूरे क्षेत्र और वहां के लोगों को अपने अधीन करने के लिए किया है। इस उग्रवादी समूह ने विरोधी गांव वालों की पानी की सप्लाई काट दी थी। उग्रवादी समूह ने जानबूझकर बड़े इलाकों में पानी भरकर (बाढ़ें लाकर) लोगों को विस्थापित किया। हाल ही में, उन्होंने इराकी पनबिजली बांधों, खास तौर से मोसुल बांध को निशाना बनाया है। अगर यह बांध फटता है तो बगदाद के 5 लाख लोगों की जल समाधि निश्चित है।

इसी तरह के तनाव तज़ाकिस्तान में स्थित रोगुन बांध और दी ग्रैण्ड इथियोपियन रिनेसां बांध जैसे बड़े पनबिजली प्रोजेक्ट में देखे गए हैं। पड़ोसी देशों ने इन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा, इन मामलों में ऊर्जा और कृषि हित आपस में टकरा रहे हैं।

यह सही है कि मीठे पानी की कमी बढ़ती जा रही है मगर पूरे मामले को 'जल युद्ध' मान लेना गलत होगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी एक-दूसरे के सहयोग के अवसर भी प्रदान करता है। पानी साझा करने से राष्ट्र पास-पास आए हैं। 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध के बावजूद बरकरार रहा और आज भी लागू है।

दूसरे शब्दों में, पानी परस्पर सहयोग और टकराव के निपटारे में भूमिका निभा सकता है और निभाना चाहिए। विश्व की 90 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जो नदियों और झीलों को साझा करते हैं। 148 देशों में कम से कम एक नदी का कछार सरहद के आर-पार है। 1820 से 2007 के बीच लगभग 450 अंतर्राष्ट्रीय पानी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 में युरोप में राष्ट्र संघ आर्थिक आयोग के तत्वाधान में हुआ पानी समझौता इसका एक उम्दा उदाहरण है। पानी तक साझा पहुंच राष्ट्रों के बीच टकरावों को लेकर संवाद का आधार बन सकती है मगर यदि इन्हें संबोधित न किया गया तो ये क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी तरह के सहयोग का एक हालिया उदाहरण चाड झील के कछार को साझा करने वाले देशों के बीच समझौते का है। चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया ने चाड झील में घटते पानी के समतामूलक बंटवारे के लिए 1964 में एक आयोग का गठन किया था जिसमें आगे चलकर लीबिया और सेंट्रल अफ्रीकन गणतंत्र भी शामिल हुए। इस वर्ष इस आयोग की कार्यसूची में क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल कर लिया गया।

कहने का मतलब यह है कि जल-कूटनीति एक सच्चाई है। पानी उपयोग का साझा प्रबंधन क्षेत्रीय सहयोग हासिल करने का एक अच्छा और महत्वपूर्ण औज़ार बन सकता है। 2015 और उसके आगे भी कूटनीति, अर्थनीति और वैज्ञानिक रिसर्च के ज़रिए हमें पानी के स्रोतों पर सहयोग की नज़र से ध्यान देना चाहिए बजाय टकराव के। ***(स्रोत फीचर्स)***